



तीसरा NAMASTE दिवस 2026: कोलकाता में स्वच्छता श्रमिकों का सम्मान

राष्ट्रीय मशीनीकृत स्वच्छता पारितंत्र हेतु कार्य योजना (NAMASTE) का तीसरा वार्षिक दिवस 14 जुलाई 2026 को कोलकाता के रवींद्र सदन में 'दिव्य कला मेला' के साथ मनाया गया।

NAMASTE योजना: प्रमुख तथ्य

- शुभारंभ: 2022-23 में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) तथा आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) द्वारा संयुक्त रूप से।
- उद्देश्य: सीवर एवं सेप्टिक टैंक की खतरनाक मैनुअल सफाई (मैनुअल स्कैवेंजिंग) का उन्मूलन, स्वच्छता कार्य में शून्य मृत्यु दर, वैकल्पिक आजीविका उपलब्ध कराना, 100% सुरक्षा उपकरण सुनिश्चित करना तथा सभी स्वच्छता श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ना।
- समन्वयक निकाय: राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (NSKFDC)।
- आंकड़े: भारत में अनुमानतः 58,098 सीवर एवं सेप्टिक टैंक श्रमिक (SSWs) सक्रिय रूप से नियोजित हैं।
- दिवस इतिहास: प्रथम NAMASTE दिवस 14 जुलाई 2024 को, द्वितीय 2025 में तथा 2026 में इसका तीसरा आयोजन हुआ।

NAMASTE — त्वरित तथ्य

- मंत्रालय: MoSJE एवं MoHUA (संयुक्त)
- समन्वयक निकाय: NSKFDC
- 2026 आयोजन स्थल: रवींद्र सदन, कोलकाता
- संवैधानिक आधार: अनुच्छेद 17 (अस्पृश्यता उन्मूलन)

उच्चतम न्यायालय की AI समिति द्वारा 'न्यायालयों में AI उपयोग हेतु विनियम, 2026' प्रस्तावित

उच्चतम न्यायालय की कृत्रिम बुद्धिमत्ता समिति ने न्यायपालिका में उत्तरदायी AI अंगीकरण हेतु एक व्यापक शासन ढांचा स्थापित करने के उद्देश्य से 'न्यायालयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) उपयोग हेतु विनियम, 2026' का मसौदा तैयार किया है।

मसौदा विनियम के प्रमुख प्रावधान

- मानवीय निर्णय की सर्वोच्चता: नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि किसी भी अंतिम न्यायिक परिणाम, निर्णय, आदेश अथवा तथ्य/विधि संबंधी निष्कर्ष तक केवल एल्गोरिदिक निर्णय-प्रक्रिया के माध्यम से नहीं पहुंचा जा सकता — AI के परिणाम पूर्णतः सलाहकारी एवं स्वतंत्र मानवीय मूल्यांकन के अधीन रहेंगे।
- नियामक संस्थागत ढांचा: उच्चतम न्यायालय में एक स्थायी, पूर्णकालिक शीर्ष निकाय द्वारा शासन, जिसमें उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों के कार्यरत न्यायाधीश, MeitY अधिकारी तथा साइबर/वित्त विशेषज्ञ सम्मिलित होंगे।
- अनिवार्य आनुपातिकता परीक्षण: किसी भी AI उपकरण की तैनाती से पूर्व डेटा स्रोत, साइबर सुरक्षा आधारेखा, व्याख्येयता एवं मतिभ्रम (Hallucination) के जोखिम का व्यापक तकनीकी एवं नैतिक प्रभाव आकलन अनिवार्य।
- साथ ही न्यायिक लंबन (Backlog) कम करने हेतु विशेष पीठों की स्थापना की भी घोषणा की गई।

पृष्ठभूमि

- यह मसौदा 3 जून 2026 को जारी हुआ तथा सार्वजनिक टिप्पणियों हेतु 15 जुलाई 2026 तक खुला है।

- न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा की अध्यक्षता वाली उच्चतम न्यायालय की AI समिति ने हाल ही में एक प्रकरण में AI द्वारा गढ़े गए काल्पनिक निर्णयों पर निर्भरता को चिह्नित करते हुए 'शून्य-सहनशीलता' का आह्वान किया।

सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र अब 'कर्तव्य भवन परिसर' के नाम से जाना जाएगा

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 12 जुलाई 2026 को CPWD स्थापना दिवस समारोह के दौरान घोषणा की कि नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास क्षेत्र को अब से 'कर्तव्य भवन परिसर' अथवा 'कर्तव्य भवन क्षेत्र' कहा जाएगा।

प्रमुख बिंदु

- नामकरण परिवर्तन: सभी आधिकारिक दस्तावेजों एवं संदर्भों में 'सेंट्रल विस्टा' नाम का प्रयोग बंद कर दिया जाएगा।
- 'सेवा तीर्थ': प्रधानमंत्री कार्यालय, कैबिनेट सचिवालय एवं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के कार्यालय वाले नए परिसर को 'सेवा तीर्थ' नाम दिया गया है।
- समग्र क्षेत्र: कर्तव्य पथ पर स्थित विभिन्न 'कर्तव्य भवन' कार्यालय भवन, कर्तव्य मार्ग तथा क्षेत्र में भविष्य के सरकारी भवन — सभी सामूहिक रूप से 'कर्तव्य भवन क्षेत्र' कहलाएंगे।

भारत ने UNSC अस्थायी सदस्यता (2028-29) हेतु आधिकारिक अभियान शुरू किया

भारत ने 13 जुलाई 2026 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में 2028-29 कार्यकाल हेतु अस्थायी (अस्थायी सदस्य) सीट के लिए अपना आधिकारिक अभियान शुरू किया।

प्रमुख बिंदु

- विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने इस अभियान की औपचारिक शुरुआत की घोषणा की।
- UNSC संरचना: सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी (वीटो शक्ति सहित) तथा 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जो 2 वर्षीय कार्यकाल हेतु क्षेत्रीय आधार पर निर्वाचित होते हैं।
- भारत इससे पूर्व भी कई बार अस्थायी सदस्य के रूप में सेवा दे चुका है तथा साथ ही स्थायी सदस्यता की मांग हेतु G4 समूह (भारत, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील) के माध्यम से भी सक्रिय है।

कर्नाटक ने भारत की पहली सरकार-संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय की घोषणा की

कर्नाटक सरकार ने 14 जुलाई 2026 को बेंगलुरु में Google I/O कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान भारत की पहली सरकार-संचालित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना की घोषणा की।

प्रमुख बिंदु

- उद्देश्य: AI क्षेत्र में विशेषीकृत उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान प्रदान करना, जिससे राज्य को AI प्रतिभा एवं नवाचार का वैश्विक केंद्र बनाया जा सके।
- यह घोषणा कर्नाटक की तकनीकी नवाचार में अग्रणी स्थिति (बेंगलुरु — 'भारत की सिलिकॉन वैली') को और सुदृढ़ करती है।

NIDAR 2.0: स्वदेशी ड्रोन नवाचार हेतु राष्ट्रीय चुनौती का शुभारंभ

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया (DFI) के साथ साझेदारी में 'ड्रोन अनुप्रयोग एवं अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय नवाचार चुनौती' (NIDAR 2.0, 2026-27) के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ किया।

प्रमुख बिंदु

- स्वरूप: यह एक राष्ट्रीय स्तर की नवाचार हैकाथॉन है, जो इंजीनियरिंग छात्रों को उन्नत स्वायत्त ड्रोन सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर घटकों के डिज़ाइन, प्रोटोटाइप एवं निर्माण हेतु चुनौती देती है।

- ▶ फोकस क्षेत्र: पूर्व-निर्मित एयरफ्रेम से आगे बढ़ते हुए स्वदेशी एवियोनिक्स, सुरक्षित ड्रोन संचालन बुद्धिमत्ता तथा माइक्रोचिप एकीकरण पर विशेष बल।
- ▶ यह MeitY के व्यापक 'स्वायन क्षमता निर्माण' पहल के अंतर्गत एक प्रमुख राष्ट्रीय नवाचार मंच के रूप में कार्य करता है।
- ▶ लक्ष्य: सरल ड्रोन असेंबली से आगे बढ़कर ड्रोन के 'मस्तिष्क' (सॉफ्टवेयर एवं चिप) का भारत में ही निर्माण कर एक आत्मनिर्भर घरेलू ड्रोन उद्योग स्थापित करना।

SHANTI अधिनियम, 2025 के क्रियान्वयन पर नीति आयोग की हितधारक परामर्श बैठक

नीति आयोग ने भारत के असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी हेतु मार्ग प्रशस्त करने वाले SHANTI अधिनियम, 2025 के प्रभावी क्रियान्वयन पर एक व्यापक हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की।

चर्चा के प्रमुख बिंदु

- ▶ विनियामक ढांचा: निजी क्षेत्र की भागीदारी हेतु स्पष्ट एवं सुरक्षित विनियामक प्रक्रिया विकसित करना।
- ▶ वित्तपोषण एवं बीमा: परमाणु परियोजनाओं हेतु दीर्घकालिक वित्तपोषण तंत्र तथा दायित्व बीमा कवरेज पर विचार-विमर्श।
- ▶ विनिर्माण क्षमता: घरेलू परमाणु उपकरण विनिर्माण क्षमता के विस्तार की आवश्यकता।
- ▶ जन-जागरूकता एवं परिचालन तत्परता: स्थानीय समुदायों में विश्वास निर्माण तथा सुरक्षा प्रोटोकॉल की तैयारी।
- ▶ पृष्ठभूमि: यह अधिनियम भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में निजी निवेश की अनुमति देकर स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों की प्राप्ति में तेज़ी लाने हेतु दिसंबर 2025 में पारित हुआ था।

SHANTI अधिनियम — त्वरित तथ्य

- पारित वर्ष: दिसंबर 2025
- उद्देश्य: असैन्य परमाणु क्षेत्र में निजी भागीदारी
- नोडल एजेंसी (परामर्श): नीति आयोग
- जुड़ाव: भारत के स्वच्छ ऊर्जा एवं आत्मनिर्भरता लक्ष्य

Also In News — संक्षिप्त समाचार

विंबलडन 2026: सिनर ने खिताब बरकरार रखा, नोस्कोवा महिला वर्ग की विजेता

- ▶ यानिक सिनर ने पुरुष एकल खिताब सफलतापूर्वक बरकरार रखा।
- ▶ मीरा नोस्कोवा ने महिला एकल खिताब जीता।

दिल्ली ने राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का शुभंकर 'मयूर' जारी किया

- ▶ 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में होगा।
- ▶ शुभंकर 'मयूर' राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है।

गिर वन में 6 दशक पश्चात भारतीय धूसर धनेश (Grey Hornbill) की पुनः वापसी

- ▶ गुजरात के गिर वन क्षेत्र में भारतीय धूसर धनेश पक्षी को छह दशकों से अधिक की अनुपस्थिति के पश्चात पुनः देखा गया।

लद्दाख का UAE को पहला ताज़ा खुबानी निर्यात खेप

- ▶ लद्दाख ने 14 जुलाई 2026 को संयुक्त अरब अमीरात को अपनी पहली ताज़ा खुबानी निर्यात खेप रवाना की।
- ▶ यह खेप 1,000 मीट्रिक टन की व्यापक निर्यात योजना का हिस्सा है, जो लद्दाख की स्थानीय बागवानी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगी।

तमिलनाडु ने एकीकृत डिजिटल मंच 'नलम TN' लॉन्च किया

- ▶ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने चेन्नई में प्रेसीडेंसी में इस एकीकृत डिजिटल सेवा पोर्टल का शुभारंभ किया।
- ▶ यह नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं तक एकल मंच से पहुंच प्रदान करेगा।

अरुणाचल प्रदेश में दो नई एकाकी मधुमक्खी प्रजातियां खोजी गईं

➤ यह वैज्ञानिक अध्ययन द्वारा पुष्टि की गई एक उत्साहजनक पारिस्थितिक उपलब्धि है।

➤ अशोका विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने Elaphropoda triangulata एवं Habropoda adi नामक दो नई एकाकी मधुमक्खी प्रजातियों की खोज की।
➤ यह खोज पूर्वोत्तर भारत की समृद्ध एवं अल्प-अध्ययनित जैव विविधता को रेखांकित करती है।

भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन की ISS यात्रा प्रस्तावित

➤ भारतीय मूल के नासा अंतरिक्ष यात्री अनिल मेनन अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) हेतु एक मिशन पर जाने वाले हैं।
➤ यह भारतीय मूल के अंतरिक्ष यात्रियों की वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में निरंतर बढ़ती भागीदारी का प्रतीक है।

Place in News — फ्रांस (राजधानी: पेरिस)

14 जुलाई को फ्रांस अपना राष्ट्रीय दिवस 'बैस्तील दिवस' (Bastille Day) मनाता है, जो 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्तील दुर्ग पर हुए हमले की स्मृति में मनाया जाता है।

राजनीतिक विशेषताएं

- स्थिति: पश्चिमी यूरोप में स्थित, यूरोपीय संघ का संस्थापक सदस्य तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य (वीटो शक्ति सहित)।
- सीमावर्ती देश: बेल्जियम, जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड, इटली, स्पेन सहित कई यूरोपीय देशों से सीमा साझा करता है।
- सीमावर्ती जल निकाय: उत्तर में इंग्लिश चैनल, पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण-पूर्व में भूमध्य सागर।
- शासन प्रणाली: अर्ध-राष्ट्रपतीय गणतंत्र, राजधानी पेरिस।

भौगोलिक विशेषताएं

- राष्ट्रीय दिवस: 14 जुलाई (बैस्तील दिवस), 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के दौरान बैस्तील दुर्ग पर हमले की स्मृति में।
- प्रमुख पर्वत श्रृंखला: आल्प्स (पूर्व), पिरेनीज़ (दक्षिण-पश्चिम, स्पेन सीमा)।
- प्रमुख नदियां: सीन, लॉयर, रोन एवं गारोन्।
- भारत से संबंध: भारत-फ्रांस व्यापक सामरिक भागीदारी, रक्षा (राफेल, स्कॉर्पीन पनडुब्बी), असैन्य परमाणु ऊर्जा एवं अंतरिक्ष सहयोग के क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोगी।

